Demand to construct Satyagrah Sthal at Pusad, Yavatmal, Maharashtra

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): महोदय, भारत स्वतंत्रता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर रहा है। यह अवसर है, इतिहास की उपेक्षित घटनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देकर प्रकाश में लाने का। ऐसा ही एक पुसद सत्याग्रह स्थल है, जो सात दशकों से उपेक्षित है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि तब भी प्रत्येक वर्ष देश भर से हजारों लोग इस स्थल को देखने आते हैं। 1930 में महात्मा गाँधी ने जब 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' शुरू किया था, तब पुसद में ऐतिहासिक 'जंगल सत्याग्रह' हुआ था। इसका नेतृत्व डा. केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। वे विदर्भ कॉंग्रेस के पूर्व सचिव तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक थे। 14 जुलाई, 1930 को वे सैकड़ों सत्याग्रहियों के साथ नागपुर से रवाना हुए। वर्धा सहित अनेक स्थानों से होते हुए वे यवतमाल में पुसद पहुँचे। 21 जुलाई को सत्याग्रह की तिथि वार काउंसिल ने निश्चित की। उस दिन सत्याग्रह स्थल पर वे दस हज़ार लोगों के साथ पहुँचे। विदर्भ में 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' 'जंगल सत्याग्रह' के रूप में आयोजित किया गया था। डा. हेडगेवार गिरफ्तार हुए, उन्हें एक वर्ष को सश्रम कारावास की सज़ा मिली। इस सत्याग्रह का महत्व इसलिए भी था कि इसने पहले चरण में मृतप्राय 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में जान फूंकने का काम किया। पूरे विदर्भ में डा. हेडगेवार के समर्थन में रैली निकाली गई। इसके बाद सत्याग्रहियों ने शराब की दुकान पर भी छापा मारना शुरू कर दिया। यह स्थल जंगल के बीच में सिर्फ एक साइनबोर्ड के साथ उपेक्षित है। यहाँ पर सत्याग्रह स्थल तथा 1930 के सत्याग्रह की यादों का म्यूजियम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विकसित किया जाना उचित होगा।

MR. CHAIRMAN: Shri Anil Desai; not present. The next Special Mention is of Ms. Dola Sen.

Demand to provide adequate allocation to National Infrastructure Pipeline

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, investments in infrastructure have a multiplier effect on economic growth. In April 2020, the task force for National Infrastructure Pipeline (NIP) submitted recommendations to the Finance Ministry earmarking a total investment of Rs. 110 trillion outlaying energy, roads, railways, and urban projects.

Envisaging that 50 per cent of the total funding for NIPs would come from Government, it is also assumed that the Government would increase the capital expenditure by 10 per cent each year. But Covid-19 has substantially affected the revenue flows of the Government leading to a paucity of fiscal potential for undertaking such investment expenditure as proposed. The various financiers of the NIP are themselves struggling which leaves NIP a utopia.

According to the Centre for Monitoring Indian Economy, new project announcements from the Government have decreased drastically since March, 2020.